लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-31 मार्च 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -38

"गिले शिकवे भुलाकर प्रेम व सौहार्द बढ़ाने का अवसर है होली

: सुवचन

सुशासन से मिली विकास को गति

2

शिक्षा में अनुमान से अधिक खर्च करेगी सरकार

6

प्रेम व सौहार्द बढ़ाने का पर्व होली

8

बजट: 2022-23

प्रगति के नए आयाम

मणि-माणिक महंगे किए, सहजे तृण, जल, नाज

विशेष प्रतिनिधि

अर्थतंत्र की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने अपने एक दोहे में लिखा है- 'मणि-माणिक महंगे किए, सहजे तृण, जल, नाज। तुलसी सोइ जानिए राम गरीब नवाज।' अर्थात पहली वरीयता पशुओं के चारे को, दूसरी जल को और तीसरी अन्न को। जो भी प्रजा हितकारी ऐसी आदर्श व्यवस्था को अंजाम देता है- वही सच्चा गरीब-नवाज़ राम है।

कहने का भाव यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट में आम जन की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रख कर हरियाणा प्रदेश के समग्र विकास का खाका तैयार किया है। सबकी सलाह पर तैयार किया गया सबका बजट आने वाले दिनों में निश्चित रूप से विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

बजट में कोई नया कर नहीं

वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का कर रहित बजट पिछले वर्ष के 1,53,384.40 करोड़ रुपए की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक है। इस बार का बजट पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के अंत्योदय के मूलमंत्र पर केंद्रित है और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ऊपरी पायदान पर लाया जाए।

वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने मित्तव्यवयता पर भी विशेष फोकस किया है। मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार के नए कर लगाने का जिक्र नहीं किया है जो दर्शाता है कि बजट पूरी तरह से संतुलित व समावेशी विकास का प्रतीक है।

उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य के सभी वित्तीय मानदंड नियंत्रण में हैं। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। बजट में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए 61,057.35 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया है जो वर्ष 2021-22 में 48 265.49 करोड़ रुपए था इससे पूंजीगत हिस्सा 31.5 प्रतिशत से बढक़र 34.4 प्रतिशत होना अनुमानित है। इससे प्रदेश में आधारभूत संरचना के विस्तार को और मजबूती मिलेगी जो आगे अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। इसी प्रकार, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में बड़ी वृद्धि की गई है। इससे प्रदेश में मानव संसाधन विकसित होगा और वह भी आर्थिक विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाएगा।

बजट में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 3.5 प्रतिशत की सीमा को 2.98 प्रतिशत के भीतर रखा गया है। बजट में संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के लिए वर्ष 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य का भी विशेष ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री ने सतत विकास से संबंधित योजनाओं के लिए 1,14,444.7 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो शायद अब तक किसी भी राज्य ने अपने बजट में नहीं किया है। ऐसा कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार तीसरी बार अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन को भी दर्शाया है।

अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने का लक्ष्य

राजकोषीय घाटे को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित सकल घरेलू उत्पाद दर 4 प्रतिशत की निर्धारित सीमा की बजाय मुख्यमंत्री ने इसे 3.4 प्रतिशत की सीमा के भीतर समेटे रखा। बजट में प्रधानमंत्री मोदी की देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन ले जाने के लक्ष्य को भी तवज्जो दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4 प्रतिशत है मुख्यमंत्री ने इसे वर्ष 2022-23 में 4 प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य रखा है।

बजट में 5327.56 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की संभावना दर्शायी गई हैं। आगामी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में संचित पूंजी निवेश 66,384.90 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में पेश किया गया है। पात्र व्यक्ति को मुफ्त में कोई चीज देने की बजाए उसे अपने पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर दिया जा रहा है। यही देश और जनता के हित में है। नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

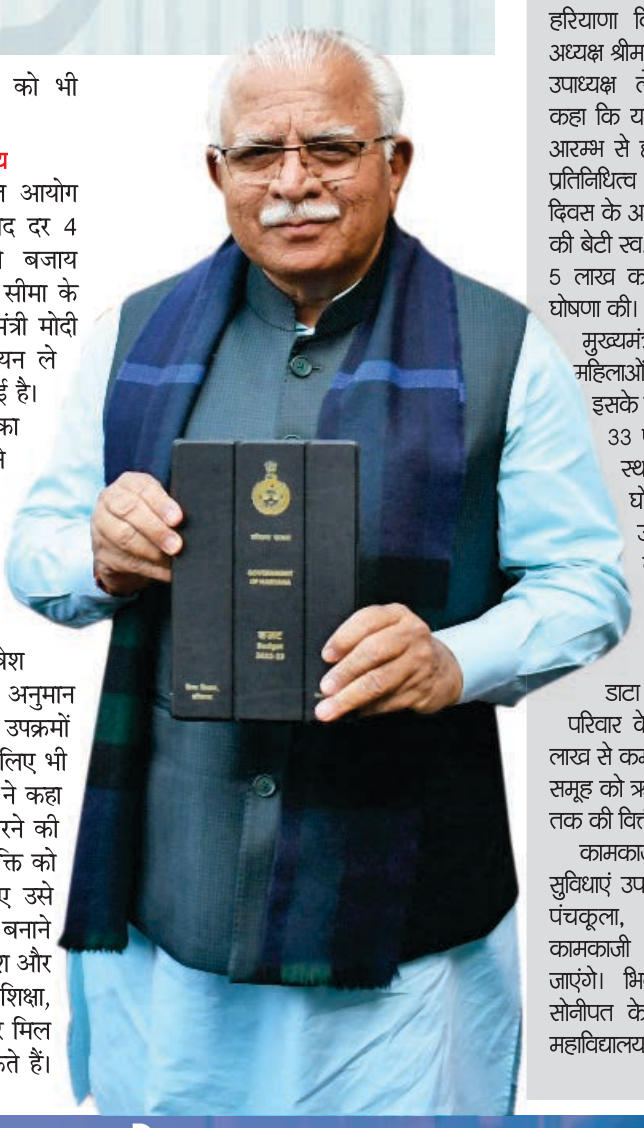

महिला शक्ति को समर्पित बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में प्रस्तुत किए बजट को महिलाओं को समर्पित किया। उन्होंने अपने बजट अभिभाषण में हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नों देवी तथा प्रथम महिला उपाध्यक्ष लेखवती जैन का जिक्र किया। कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि आरम्भ से ही इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा की बेटी स्व. श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम 5 लाख का पुरस्कार आरम्भ करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की और अधिक भागीदारी हो, इसके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की बजाए 50 प्रतिशत स्थानों पर भागीदारी बढ़ाने की घोषणा भी की। महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए 'हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना' की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके लिए परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर महिला एवं उसके परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय 5 लाख से कम आधार मानकर स्वयं सहायता समूह को ऋण के रूप में तीन लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कामकाजी महिलाओं को सस्ती आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा की। पंचकूला, गुरुग्राम व फरीदाबाद में कामकाजी महिला आवास स्थापित किए जाएंगे। भिवानी के कुड़ल व छप्पार तथा सोनीपत के गन्नौर में तीन नये महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई।

प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प

हरियाणा राज्य की शासकीय व्यवस्था में क्षेत्रवाद व भाई भतीजावाद अब बीते जमाने की बात हो चुकी हैं। वर्तमान बजट में इसकी झलक साफ तौर से देखने को मिली। प्रदेश के लोगों ने अनेक प्रकार के वादों का दंश लंबे समय तक झेला है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल लोगों को उस भय से स्थाई मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उनका मानना है कि आजादी का अमृत महोत्सव सही मायने में तभी सार्थक होगा जब उनके प्रदेश का हर परिवार 'आत्मनिर्भर' होगा।

प्रदेश का कोई कोना विकास से अछूता ना रहे इसके लिए बजट से पूर्व सबकी सलाह ली गई। इतना ही नहीं प्रस्तावित बजट पर भी विधानसभा द्वारा गठित विभिन्न कमेटियों से सहमति ली गई। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने लोकतांत्रिक मूल्यों का पूर्णरूपेण निर्वहन करते हुए प्रदेश में यह नई परंपरा शुरू की।

राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास हो। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इस परिप्रेक्ष्य में विगत दिनों बैठकों के जरिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, उद्योगपतियों एवं कारोबारियों से भी परामर्श किया।

राज्य सरकार चाहती है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में रोजगार का कोई संकट न रहे। इसके लिए न केवल सरकारी क्षेत्र को समृद्ध किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं।

अन्तोदय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनके जरिए अति गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सरकार चाहती है कि परिवार फ्री मिलने वाली सहायता के भरोसे न रहें। वे कुछ काम करें और अर्थ व्यवस्था में सहयोग दें। बजट में छोटे किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने व कर्जमुक्त होने की राह दिखाई गई है। इससे छोटी जोत वाले किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सरकार ने बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है।

बजट में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य व रोजगार पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा तंत्र में गुणात्मक सुधार हो ताकि उसके जरिए देश-विदेश में रोजगार उपलब्ध हो सकें। राज्य सरकार का प्रयास है कि मेडिकल शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चों को इसके लिए दूसरे देशों में न जाना पड़े। इसके लिए मेडिकल कालेज व नर्सिंग कालेज खोले जा रहे हैं। चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ करने पर मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने तथा मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने की योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाने व राजकोषिय घाटा कम करने को लेकर गंभीर है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए राजकोष को ध्यान में रखते हुए हर तरह से दरियादिली दिखाई है। विकासोन्मुखी एवं नपा तुला बजट मुख्यमंत्री के अर्थ कौशल का भी परिचय देता है।

-मनोज प्रभाकर

संपादकीय

सुषमा स्वराज की स्मृति में पुरस्कार

हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की यशस्वी बेटी दिवंगत सुषमा स्वराज की स्मृति में प्रति वर्ष सम्मान-पुरस्कार देने की घोषणा का सर्वत्र स्वागत हुआ है। राजनीति के वर्तमान माहौल में कुछ ऐसे नेताओं को याद करना सुकून देता है जो अपने समय में सकारात्मक भाव रखते हुए संतुलन बनाए रखते थे।

इनमें से एक नाम सुषमा स्वराज का है। सुषमा देश की विदेश मंत्री, सूचना-प्रसारण और मानव संसाधन मंत्री रही थीं। आतंकवाद पाकिस्तान, चीन, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति आदि ढेरों ऐसे विषय थे जिनके बूते वे खबरों में बनी रह सकती थीं। पद के अनुरूप उन्हें मीडिया में विशिष्ट 'कवरेज' भी यकीनन मिल सकती थी। लेकिन वे इससे दूर रहीं। वे अपनी गरिमापूर्ण छवि का निर्माण करने में सफल रही थीं।

विदेशों में फंसे भारतीयों का प्रश्न हो या सीमा पार के किसी व्यक्ति की व्यथा-कथा या फिर चंडीगढ़ आई पाक-छात्राओं के लिए समुचित सम्मानजनक प्रबंधों का प्रश्न, सुषमा ने शालीनतापूर्वक अपने सभी दायित्व निभाए और उन पर अनावश्यक कवरेज से भी बचाव रखा।

सुषमा अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री की कार्यशैली व 'विज़न' को बखूबी समझती थीं। उन्हें यह भी मालूम था कि 'ब्रीफ़' से बाहर जाकर स्वतंत्र छवि बनाने के प्रयास राजनीति में कितने जोखिम भरे होते हैं।

सुषमा की राजनैतिक यात्रा का शुरुआती दौर याद आता है। अम्बाला छावनी के एसडी कॉलेज की छात्रा सुषमा, जिसे लगभग हर भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना होता था और हर प्रतियोगिता में पहला स्थान पाना होता था।

25 वर्ष की उम्र में वह हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में ले ली गई थीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा की वाक शैली के कायल थे। वह कई बार भविष्यवाणियां कर देते थे। याद है जब उन्होंने सुषमा की एक चुनाव सभा में अपने भाषण के मध्य ही कह दिया था 'यह छोरी केंद्रीय स्तर पर नेता बनेगी और कोई बड़ी बात नहीं कि एक दिन प्रधानमंत्री भी बन जाए।'

सुषमा एसडी कॉलेज अम्बाला छावनी से स्नातक स्तर और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई के बाद राजनीति में सक्रिय हो गई। शुरुआती पारी विद्यार्थी-परिषद से खेली। 1979 में वह 27 वर्ष की उम्र में हरियाणा जनता पार्टी की अध्यक्ष बनीं। तीन बार विधायक रहीं। सुषमा 1987 से 1990 तक हरियाणा की शिक्षा मंत्री भी रही। अक्तूबर 1998 में वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं।

हरियाणा सरकार ने उनके नाम से पुरस्कार शुरू कर एक सराहनीय कार्य किया है।

- डॉ. चन्द्र त्रिखा

मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी आर्थिक सहायता

चिकित्सा आधार पर मदद के लिए पोर्टल लॉन्च

राज्य सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इससे यह प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओ को देखते हुए इस प्रकिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

उन्होंने ने कहा कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदको को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम ने पोर्टल की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ज्यों ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा त्यों ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है।

महिलाओं को मिला विज्ञान रत्न पुरस्कार

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 11 वैज्ञानिक समानित

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल स्तर पर तंत्र विकसित किए जाने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश को विश्व स्तर पर नई पहचान मिलेगी। जिससे ''न्यू इंडिया मॉडर्न इंडिया'' का स्वरूप तैयार होगा। राज्यपाल यहां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राजभवन में साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित हरियाणा विज्ञान रत्न एवं हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे।

बंडारू दत्तात्रेय ने 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार दिया, जिनमें दो महिला वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि महिलाओं को इस पुरस्कार से नवाज़ा किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में सशक्त करने के लिए हरियाणा सरकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है और हरियाणा की महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति की और अग्रसर हैं। इसके अलावा कोरोना काल में भारत के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की वैक्सीन तैयार करने का कार्य किया जो विश्व के 90 से अधिक देशों में भेजी गई है। यह भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया अद्भुत और बेहतरीन कार्य है। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एन.सी.आर. क्षेत्र में 191 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सिटी तथा 85 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

युवा वैज्ञानिक को पुरस्कार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने जीवन को सरल बनाने का काम किया है। वर्तमान अनुकूल नए अनुसंधानों की खोज में दूसरे ग्रहों तक पहुंच विज्ञान की प्रगति का द्योतक है। उन्होंने कहा कि समाज के विशेष वर्ग ने जीवन की दिशा बदलने का कार्य किया है। जीवन में छोटी-छोटी घटनाएं क्यों और कैसे होती है और इनके क्या परिणाम निकलेंगे यह वैज्ञानिकों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और वैज्ञानिक इसकी खोज की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है

विज्ञान को बढ़ावा

हरियाणा के गृह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल विज ने कहा कि भौतिकी में शोध के प्रयास किए जा रहे हैं इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा से बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जा रहा है। विज ने कहा कि खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी को बढ़ावा देने के लिए कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की गई है। इसके अलावा ग्यारहवीं कक्षा से विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक हजार से तीन हजार पांच सौ रुपए तक की छात्रवृत्ति तथा जिला स्तर पर विज्ञान प्रतियोगिताएं और साइंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है।

इनको मिले सम्मान

हरियाणा के उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रो. नीरज जैन तथा प्रो. मुकेश जैन को 2019 के लिए, प्रो. मोती लाल मदान व डॉ. सुशीला मान को वर्ष 2020 के लिए तथा डॉ. चेतन प्रकाश कौशिक व डॉ. इलोरा सेन को वर्ष 2021 के लिए 'हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में चार लाख रुपए की नकद राशि प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। डॉ. पूजा देवी व डॉ. राम जिवारी को वर्ष 2019 के लिए, डॉ. पवन कुमार व सतीश खुराना को वर्ष 2020 के लिए तथा डॉ. कल्पना नागपाल को वर्ष 2021 के लिए 'हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए की नकद राशि प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।

-संवाद ब्यूरो

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

बजट अनुमान 2022-23 के लिए, यह जी.एस.डी.पी. का 24.51 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए जी.एस.डी.पी. के 33.3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 40 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा के डॉक्टरों हेतु आरक्षित की गई हैं।

सुशासन से मिली विकास को गति

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण

राज्यपाल श्री बंडारू दतात्रेय ने कहा कि प्रदेशवासियों की आशा एवं आंकक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वायत्तता, संरक्षण, स्वावलंबन, सुरक्षा, स्वामित्व, समाधान और सुशासन के माध्यम से प्रदेश के चहुंमुखी विकास को नए आयाम देने के लिए निरंतर अग्रसर है।

आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आरंभ हुए हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल महोद्य ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद की सोच से ऊपर उठकर प्रदेश के सन्तुलित, सतत और समान विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन अभियान के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई-गवर्नेंस का रास्ता अपनाया जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और प्रदेश के कमजोर, गरीब व आम आदमी को भी प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो। राज्य सरकार ने 'सुशासन से सेवा' के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप 'सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास' और 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' के मूलमंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के ''आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है'', के सिद्धांत की पालना करते हुए क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र व हर वर्ग का समान विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पंचकूला से पलवल तक और सिरसा से फरीदाबाद तक बदलाव की इस सुखद बयार को महसूस किया जा सकता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' शुरू की है। गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' करने की हरियाणा की योजना को केन्द्र सरकार ने 'स्वामित्व योजना' के रूप में पूरे देश में लागू किया है। 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना का अध्ययन करने के लिए भी एक केन्द्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया था।

उन्होंने कहा कि ''शासन कम, सुशासन ज्यादा'' को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस की नई-नई पहलें की हैं। ई-गवर्नेंस का यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुका है। इस एकमात्र दस्तावेज से लोगों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिलेगा और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जन्म-मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली पाई-पाई सही लाभार्थी तक पहुंचाने और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए 'डी.बी.टी.' सुविधा शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, जनता के प्रति प्रशासन की जबाबदेही तय करने और समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' (आस) शुरू किया गया है और इससे 570 सेवाओं को जोड़ा गया है। आवेदक को यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है तो उसकी अपील स्वत» ही उच्चाधिकारी को और फिर 'सेवा का अधिकार आयोग' को भी चली जाती है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता एवं स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 43 विभागों के 214 कॉडर में लागू की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि अब हरियाणा विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से अग्रसर है।

-संवाद ब्यूरो

पंचायत में होगी महिलाओं की 'चौधर'

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में वर्ष 2022-23 के बजट को महिलाओं को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की और अधिक भागीदारी हो, इसके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की बजाय महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों पर भागीदारिता बढ़ाने की घोषणा भी की।

इसके अलावा, महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए एक नई योजना 'हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना' की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके लिए परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर महिला एवं उसके परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय पांच लाख से कम आधार मानकर स्वयं सहायता समूह को ऋण के रूप में तीन लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन वर्ष तक ब्याज में सात प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कामकाजी महिलाओं को भी मनोहर सौगात देते हुए सस्ती आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा की और इसके लिए पंचकूला, गुरुग्राम व फरीदाबाद में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान 'सहभागिता' के माध्यम से तीन महिला आश्रम स्थापित करने की सम्भावनाएं तलाशने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।

नारी शक्ति को मिले आर्थिक आजादी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किया गया आम बजट नारी शक्ति को आर्थिक आजादी दिलाने का आधार है। यह बजट नारी शक्ति के आगे बढ़ने के अनुकूल माहौल देने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग को 33.7 प्रतिशत अधिक बजट आबंटन होने से कुपोषण से निपटने और महिलाओं के पोषण स्तर में बढ़ोतरी के लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग को 2,017 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन होने से जोखिम श्रेणी में आने वाले बच्चे, महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम होगा।

कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, हरियाणा

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ महिलाएं बखूबी उठा रही हैं। मुख्यमंत्री की सोच है कि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिलें और वे आत्मविश्वास व सम्मान के साथ आगे बढ़ें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा बेटी की शादी में सहयोग के लिए माता-पिता को आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करती है। योजना के तहत 71 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है।

क्या है योजना

योजना के तहत, सरकार विधवाओं/निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं (गरीबी रेखा से नीचे और जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है) को 51 हजार का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति,डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपए का शगुन मिलता है। स्पोर्ट्स वुमेन (किसी भी जाति/कोई भी आय) व अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित), जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलता है। वहीं, सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर 51 हजार रुपए का शगुन मिलता है। अगर पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपए, अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो 51 हजार रुपए की मदद की जाती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए saralharyana.gov.in पर जाएं और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुदान के लिए आवेदन करें। इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि शादी के तीन माह बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शगुन योजना की अन्य राज्यों से तुलना

राज्य	राशि (रुपयों में)
हरियाणा	71,000
पंजाब	51,000
हिमाचल	31,000
दिल्ली	30,000
उत्तर प्रदेश	51,000
मध्य प्रदेश	51,000

जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी-दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ नये नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय।

प्रदेश के सभी जिलों में ई-लाइब्रेरी सुविधा युक्त जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय।

हरियाणा बजट 20
सतत एवं समग्र विक

'बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे न कोय तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय'

प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने सूर्य के माध्यम से अच्छे राजा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, तो उसे कोई नहीं देखता परन्तु वही सूर्य जब जल बरसाता है, तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उसी कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है कि राजा को प्रजा से उतना ही कर ग्रहण करना चाहिए, जो न्याय पूर्ण हो। साथ ही कर-रूप में प्राप्त धन को उसे ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जिससे प्रजा का कल्याण हो।

बदलेगी खेत खलिहान की दशा

वर्ष 2022-23 का बजट निश्चित रूप से किसानों की दिशा व दशा को बदलेगा। बजट न केवल अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेगा, बल्कि आने वाले 25 सालों में हरियाणा के विकास को तेज गति प्रदान करने वज्र बजट है। बजट में किसानों का बागवानी व पशुपालकों करने वालों का विशेष ध्यान रखा गया है। कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र हेतू 5988.76 करोड़ रुपए के आंवटन का प्रस्ताव है जोकि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 27.7 प्रतिशत अधिक है।

जैविक खेती को बढ़ावा : बागवानी को बढ़ावा देने के बारे में भी सरकार गंभीर नजर आई है। जनता को जहर युक्त उत्पादों से निजात दिलाने व भूमि की सेहत को बचाने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दे रही है। इसको बढ़ावा देने और किसानों को इस खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उदेश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान भी बजट में किया है।

बजट में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 कलस्टर में शुरू किया जाएगा। निश्ति रूप से यह बजट खेती में किसानों को नई पहचान देगा। प्रत्येक कलस्टर में 25 एकड़ भूमि को भी प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण के लिए भिवानी में ''क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र'' की स्थापना की जा रही है। यही नहीं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला-सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देने का काम होगा। इसी प्रकार, गर्मी सीजन के मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी।

फसल समूह विकास कार्यक्रम : फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना के लिए सहायता सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसे ही, ''फसल विविधिकरण कार्यक्रम'' के तहत 20,000 एकड़ में फसल विविधिकरण का लक्ष्य तथा किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित वर्ष 2022-23 के बजट में प्रस्तुत किया गया है।

प्रोत्साहन राशि

प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन : बजट में सरकार ने एम्ब्रयो ट्रांसफर टैक्नॉलोजी से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। अंत्योदय परिवार जिनके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि या स्थान नहीं है, उन परिवारों को ग्राम पंचायत की भूमि पर एक सांझा शैड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नये बजट के अनुसार बजट अनुमानों में मत्स्य पालकों को भी ''किसान क्रेडिट कार्ड'' की सुविधा, भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव है।

चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

हालीय बजट में लोगों की सेहत का विशेष ख्याल रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक काडर बनाया जाएगा। इसमें डाक्टर सिर्फ क्लिनिकल ड्यूटी करेंगे। इसके लिए सेवा एवं शर्तें अलग से तय की जाएंगी। विशेष काडर तैयार होने से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य डाक्टरों को सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित करना है।

पीएचसी में आयुष सुविधाएं मिलेंगी: बजट योजना के मुताबिक जिला अस्पताल व पीएचसी को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक हासिल करने के लिए उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। वैलनेस सेंटर के रूप में स्थापित की जा रही पीएचसी में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में निजी अस्पताल खोलने वाले डाक्टरों को वित्तिय संस्थानों से लिए गए कर्ज़ पर तीन साल के लिए दो प्रतिशत ब्याज की सहायत प्रदान की जाएगी।

आयुष्मान भारत योजना का लाभ: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। परिवार पहचान पत्र का डाटा इस्तेमाल करके सरकार नई से नई योजनाएं ि यान्वित कर रही है। परिवार पहचान पत्र के डाटा में 1 लाख 80 हजार से कम आय वर्ग में एससी के 29 प्रतिशत परिवार और बीसी के 34.5 प्रतिशत परिवार आए हैं। अब 1 लाख 80 हजार से कम आय वर्ग के प्रत्येक परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक इस योजना के अंतर्गत करीब साढ़े 15 लाख लोग आते थे लेकिन अब 28 से 30 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।

दिव्यांगों को इलाज में मदद: आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के सभी ईएसआई अस्पताल भी आएंगे। इसको लेकर सहमति बन गई है। इसके अलावा 3 लाख रुपए से कम आय वाले दिव्यांगजनों के इलाज की हरियाणा में अलग से व्यवस्था की जाएगी।

मेडिकल सीटें बढेंगी: स्वास्थ्य क्षेत्र में और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, प्रत्येक जिले में 1 मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। इस वर्ष पलवल, पंचकूला, चरखी दादरी और फतेहाबाद में एक-एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। इससे प्रदेश में कुल 3 हजार मेडिकल छात्रों की सीटें हो जाएंगी, जो वर्ष 2014 में महज 700 थी।

खेलों में चमकेगा हरियाणा

प्रदेश के इतिहास में पहली बार 540 करोड़ के बजट का प्रावधान खेलों पर किया गया है । खेलो इंडिया में 250 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। नए बजट के तहत प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने में आसानी होगी। राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की योजना है।

खेलों को बढ़ावा देता नजर आता यह बजट हरियाणा की तस्वीर बदलने में कारगर साबित होगा। प्रदेश में नए बजट के तहत 1100 नर्सरी स्थापित होंगी वहीं मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब भी स्थापित किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले एक साल में एक हजार युवाओं को साहसिक गतिविधियों में ट्रेंड किया जाएगा।

नए बजट के तहत सोनीपत स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल आफ स्पोर्ट्स कैंपस में यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है इस यूनिवर्सिटी में अस्सी प्रतिशत हिस्सेदारी हरियाणा के लिए रहेगी। पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में सरकार राष्ट्रीय सत्र का वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित कर रही है। इसी तर्ज पर करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम के खेल स्टेडियम में भी यह सेंटर स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना है। इस केंद्र में वैज्ञानिक और प्रशिक्षण के अलावा स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन और स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी देशी सुविधाएं उपलब्ध होगी। पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की भी सरकार की योजना है।

प्रदेश के एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट के लिए विदेश रोजगार प्लेसमेंट सैल की स्थापना।

ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवा के दौरान कम से कम 70 प्रतिशत दिव्यांग हो जाते हैं, उनके आश्रितों को एक्सग्रेशिया के नियमों के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति।

022-23 स का लक्ष्य

बजट के मुख्य बिंदु

- बजट न केवल अर्थव्यवस्था को वज्र जैसी शक्ति प्रदान करेगा, बल्कि आने वाले 25 सालों में प्रदेश के विकास को तेज गति प्रदान करने का आधार भी बनेगा।
- राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में जी.एस.डी.पी. का 2.99 प्रतिशत रहने का अनुमान ।
- बजट अनुमान 2022-23 में जी.एस.डी.पी. के 0.98 प्रतिशत तक और कम होने का अनुमान है।
- पशुपालन व डेयरी में स्वरोज़गार के लिए एक लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का लक्ष्य।
- प्रदेश में हैफेड द्वारा गुड़ इकाइयां स्थापित करने का निर्णय।
- सभी जिलों में दूध व अन्य खाद्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं।
- प्रदूषण कम करने के लिए हर जिले में हॉट स्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदलने का लक्ष्य।
- प्रमुख पर्यावरणविद् दर्शन लाल जैन के नाम पर तीन लाख रुपए तक का पुरस्कार।
- प्रदेश में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र।
- ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ईको-टूरिज्म नीति।
- हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष-गणना और जियो टैगिंग।
- कालका से कलेसर तक 150 कि.मी. लंबी नेचर ट्रेल की स्थापना।
- प्रदेश में दस नई हाइटेक नर्सरियां विकसित करने का निर्णय।
- आठवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड व पुरस्कार।
- सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ट्विनिंग प्रोग्राम।
- प्राचीन भाषाओं और हस्तलिपि में सीखने, अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान।
- हर खण्ड में टी.बी. जांच के लिए मॉलिक्यूलर टैस्टिंग लैब की सुविधा।
- पीजीआईएमएस, रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा।
- कैथल, सिरसा और यमुनानगर में नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना आरंभ।
- पलवल, चरखी-दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा।
- ऐलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना।
- एड्स पीड़ितों को 2250 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता।
- औद्योगिक क्षेत्रों में दोहरी ट्रैक प्रणाली के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र।
- दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली से 44 नई ट्रेड यूनिट्स को जोड़ना।
- निजी क्षेत्र में रोज़गार के लिए 200 रोज़गार मेलों का लक्ष्य।
- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम का गठन।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में 20,000 नये घरों का निर्माण।
- उचित मूल्य की दुकानों को सांझा सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने का विकल्प।
- राज्य में सभी पूर्व अर्ध सैनिक बलों को पंजीकृत करके पूर्व सैनिकों के समान लाभ देने का निर्णय।
- गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए 5,000 रिचार्ज बोरवैल निर्माण का लक्ष्य।
- माइनरों पर पुलों के निर्माण के लिए दूरी का मानदंड 1,000 मीटर से कम करके 500 मीटर।
- सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।
- लोगों को प्वाइंट-टू-प्वाइंट परिवहन सुविधा के लिए नई मैक्सी कैब नीति।
- फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।
- करनाल व भिवानी हवाई पट्टियों की लंबाई 3,000 फुट से बढ़ाकर 5,000 फुट करना।
- नारनौल में हवाई पट्टियों पर नाइट लैंडिंग की सुविधा।
- अग्निशमन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए बजट में पांच गुणा बढ़ोतरी।
- लौहगढ़ को पर्यटन केंद्र के रूप में उभारने के लिए हैरिटेज संग्रहालय संग्रहालय की स्थापना।
- जिला फतेहाबाद के कुणाल में पूर्व हड़प्पा स्थल पर संग्रहालय की स्थापना।

प्रमुख आवंटन (करोड़ रु.)

विभाग	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)	विकास (%)
कुल आवंटन	1,53,384.40	1,77,255.99	15.6
कृषि संबद्ध सेवाएं	5,205.94	6,497.01	24.79
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17,260.79	20,445.36	18.45
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	895.85	1,104.68	23.31
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ईएसआई, खाद्य एवं औषधि	7,613.73	8,925.52	17.23
गृह	6,057.37	6,526.29	7.74
सामाजिक न्याय और अधिकारिता, डब्ल्यूसीडी और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण	10,863.15	13,050.02	20.13
ग्रामीण विकास एवं पंचायत	3,723.93	6,826.13	83.30
परिवहन	2,902.29	3,708.20	27.77
शहरी विकास और नगर एवं ग्राम नियोजन	9,193.31	8,468.83	-7.88
उद्योग और वाणिज्य	456.22	598.20	31.12
सिंचाई और जल संसाधन	4,064.29	6,136.36	50.98
जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकी	3,899.11	4,554.39	16.80
लोक निर्माण (सड़कें और पुल)	4,199.07	4,752.02	13.17

सड़क मार्गों का विस्तार

सड़क और रेल अवसंरचना एक राष्ट्र की रीढ़ है और इसके आर्थिक विकास की संचालक शक्ति है। वर्ष 2021-22 के दौरान 130 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 6,000 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सड़क और रेल अवसंरचना क्षेत्रों के लिए 4752.02 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जो कि वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना में 59.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

सरकार ने चिह्नित स्थलों पर भीड़ कम करने के लिए 12 नए बाईपास के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत राज्य में सड़कों को चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित 2,500 किलोमीटर सड़कों में से पिछले दो वर्षों में 1,443 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान 22 अतिरिक्त आरओबी/वीयूपी का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

विभिन्न परियोजनाएं शुरू: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हरियाणा में विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में तीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे, इस्माइलाबाद-नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। अन्य चल रही परियोजनाओं में गोहाना-सोनीपत सड़क को 4-लेन, नारनौल बाईपास को 6-लेन, रेवाड़ी-नारनौल-राजस्थान सीमा सड़क को 4-लेन, पानीपत-दिल्ली सड़क को 8-लेन, रेवाड़ी बाईपास को 4-लेन, सोनीपत-मेरठ सड़क यूपी सीमा तक को 4-लेन, नई 4-लेन जींद-गोहाना सड़क, गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी सड़क को 4-लेन, साहा से शाहबाद सड़क को 4-लेन और मंडी डबवाली से चौटाला सड़क को 6 लेन करना शामिल है। अंबाला और भिवानी शहरों के लिए रिंग रोड तथा हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद शहरों के लिए बाईपास के प्रस्ताव पहले ही भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।

औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन

हरियाणा उद्योग और वाणिज्य में अग्रणी रहा है। सरकार ने गत वर्ष 'हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2021 लागू की है। गत वर्ष सरकार ने 21,800 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जो दर्शाता है कि हरियाणा देश में प्रमुख निवेश गन्तव्य के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 598.20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि है।

औद्योगिक मॉडल टाउनशिप्स में बुनियादी ढांचे के सुधार और उन्नयन के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी जाएगी। एडवांस रोबोटिक्स और नैनो प्रौद्योगिकी सहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को और बढ़ावा दने के लिए सरकार हरियाणा उद्यमिता और रोजगार नीति-2020 की तर्ज पर एक क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति लाएगी।

एचएसआईआईडीसी पानीपत में कपड़ा उद्योग के लिए एक सांझा बुनियादी ढांचे के रूप में भाप बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा। अगले तीन महीनों में सांझा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी हेतु एक उपयुक्त तंत्र बनाया जाएगा। औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और निर्यातकों की मांगों पर सरकार औद्योगिक निर्यात के लिए माल ढुलाई सब्सिडी प्रदान करेगी।

एकीकृत विमानन हब विकसित करने का प्रस्ताव: हिसार में एक एकीकृत विमानन हब विकसित करने का प्रस्ताव है। हिसार एयरपोर्ट एक एंकर का कार्य करेगा। हिसार में 7,200 एकड़ से अधिक भूमि को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के एक भाग के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेलवलपमेंट कारपोरेशन (एनआईसीडीसी) के सहयोग से एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के रूप में विकसित किया जाएगा। इस आईएमसी में वेयरहाउसिंग, कार्गो, प्रशिक्षण एवं सिमुलेशन केंद्र, एयरोस्पेस विश्वविद्यालय और एयरोस्पेस/रक्षा विनिर्माण पाक जैसी सुविधाएं होंगी। मास्टर प्लान बनाने और पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

छोटे व्यापारियों तथा व्यवसायों को प्रोत्साहन: उद्यमिता और छोटे व्यापारियों तथा व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, 'लघु उद्यमिता समर्थन निधि' योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें व्यक्तिगत या परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों या व्यापार के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए अधिकतम तीन लाख रुपए के ऋण पर पांच प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता दी जाएगी, जो प्रतिवर्ष अधिकतम 15,000 रुपए तक होगी।

गुरुकुल, झज्जर के स्वामी ओमानन्द जी के नाम पर राजकीय संग्रहालय की स्थापना। प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में हैरिटेज कार्नर स्थापित करने का लक्ष्य।

रोडवेज बेड़े में 2,000 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली शुरू की जाएगी।

हरियाणा बजट 2022-23

आम बजट 2022-23 प्रदेश के विकास को गति देने वाला है। वैसे तो यह बजट सभी वर्गों के हित को ध्यान में रख कर बनाया गया है परंतु इसमें रोजगार, उद्योग, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, नागरिक उड्डयन पर विशेष जोर दिया गया है। इससे भविष्य में युवाओं के रोज़गार व निवेश के अधिक अवसर, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, ग्रामीणों का उत्थान और एविएशन में नई टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी और राज्य का आधारभूत ढांचा मज़बूत होगा। बजट में शामिल नई नीतियां व योजनाएं जैसे पदमा, क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, डाटा सेंटर पॉलिसी, एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण नीति, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, लघु पुनरुत्थान योजना कोष आदि प्रदेश के विकास की तस्वीर बदलेगी।

दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

1100 नई खेल नर्सरियां स्थापित करने का लक्ष्य

प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए प्रदेश के इतिहास में पहली बार 550 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट से प्रदेश में खेलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के साथ-साथ ग्रामीण आंचल में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज़ पर पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान में खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय सुविधाएं, प्रशिक्षण और खाने-पीने व रहने की तमाम व्यवस्थाए उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में 1,100 नई खेल नर्सरियां खोलने का लक्ष्य रखा है।

सरदार संदीप सिंह, खेल एवं युवा मामले मंत्री, हरियाणा

मुख्यमंत्री ने बजट में बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए 7,203.31 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसमें कृषि पंपसेट के लिए 5,983 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी शामिल है। राज्य में अक्षय ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने 181 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने की योजना बनाई है। 39 नए सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य व मौजूदा 178 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।

रणजीत सिंह, बिजली एवं जेल मंत्री, हरियाणा

आम बजट दूरगामी एवं ऐतिहासिक

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट ऐतिहासिक है। इस बजट में हर क्षेत्र के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और इस बजट में पिछले बजट की तुलना में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह आम बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का काम करेगा और विकास को बढ़ाने, गरीबों एवं वंचित समूहों के उत्थान और नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही रोज़गार व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए मज़बूत मॉडल प्रस्तुत किया है।

कंवर पाल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा

बजट में रोजगार विभाग के लिए 1671.37 करोड़ रुपए और श्रम विभाग के लिए 221.97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बजट बहुत ही संतुलित और दूरगाामी है। इसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। साथ ही, बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम व रोजगार सहित हर क्षेत्र में सुधार की बात कही गई है।

अनूप धानक, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, हरियाणा

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने से पहले सभी विभागों व समाज के अन्य वर्गों से बजट पूर्व चर्चा की और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। इस बजट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 10,229.93 करोड़ रुपए और सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण के लिए 136. 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ओ.पी यादव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, हरियाणा

बजट में सभी वर्गों का रखा गया ख्याल

मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रस्तुत किए गये बजट में हर क्षेत्र के साथ सभी वर्गों का ख्याल रखा है। बजट में महिला सशक्तिकरण, किसानों की समृद्धि, डिजिटलीकरण, सहित कई अन्य क्षेत्रों में विकास लाने की तस्वीर स्पष्ट दिखाई दे रही है। बजट में किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों व महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, बजट में बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों जैसे स्वायत संस्थानों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित है।

डा. बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री, हरियाणा

शिक्षा में अनुमान से अधिक खर्च करेगी सरकार

शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक उन्नति की कुंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, शिक्षा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। राज्य ने वर्ष 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में इसे वर्ष 2025 तक ही लागू कर देने का लक्ष्य रखा है।

वर्ष 2022-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20, 250.57 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि है। बजट में कौशल विकास एवं रोजगार क्षेत्र के लिए 1671.37 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है जोकि संशोधित अनुमानों से 23 प्रतिशत अधिक है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन

उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण एन. ई. पी-2020 का एक प्रमुख घटक है। इसका अनुसरण करते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा 2023 तक मान्यता प्राप्त कर ली जानी चाहिए। सरकार का प्रस्ताव है कि सभी कॉलेजों में कम से कम दस स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए। हरियाणा को उच्च शिक्षा के मानचित्र पर लाने के लिए, राज्य विश्वविद्यालयों को भारतीय भाषाओं, भारतीय कला एवं संस्कृति, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद आदि पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि विदेशी छात्रों को आकर्षित किया जा सके। हमारी प्राचीन भाषाओं और हस्तलिपि में सीखने, अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने हेतु, इन क्षेत्रों में अध्ययन और शोध में लगे संस्थानों को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

सुरक्षित परिवहन सुविधाएं

शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित परिवहन की कमी के कारण लड़कियों का ड्रॉप आउट न हो, सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी, विशेषकर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवागमन करने वाली प्रत्येक लड़की को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना-साथी (सुरक्षित एवं सुलभ परिवहनः हरियाणा पहल) शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह सुविधा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और चिकित्सा या पैरा मेडिकल या नर्सिंग संस्थानों सहित सरकारी संस्थानों में सभी लड़कियों के लिए प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य सुविधाएं

शिक्षित एवं स्वस्थ बच्चे हमारा भविष्य हैं। सरकार का आगामी शैक्षणिक सत्र से एक नया 'स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम' शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत स्कूलों में स्कूलों में पढ़ने वाले 25 लाख विद्यार्थियों की वर्ष

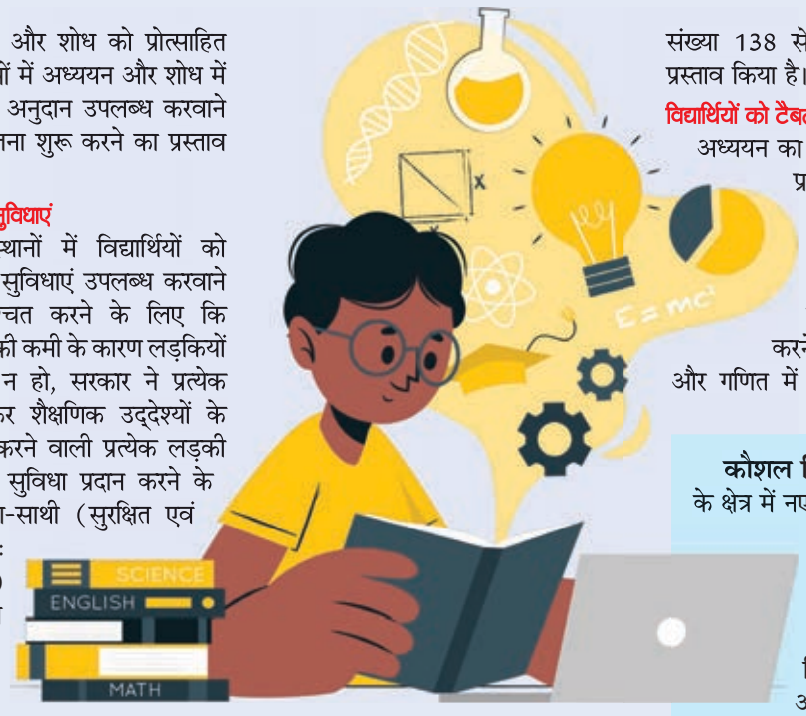

में दो बार स्वास्थ्य की जांच की जायेगी। स्कूल गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने के केंद्रों के साथ-साथ बच्चों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के केंद्रों के रूप में भी काम करेंगे और ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों के साथ जोड़े जाएंगे। राज्य में संस्कृति मॉडल स्कूलों के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का रूझान बढ़ा है। इनकी उपयोगिता और लोकप्रियता के दृष्टिगत सरकार ने इनकी संख्या 138 से बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है।

विद्यार्थियों को टैबलेट

अध्ययन का उच्च स्तर प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए सरकार का आठवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू करने का प्रस्ताव है। भौतिकी और गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे प्रख्यात विज्ञान संस्थानों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर विषयवार ओलंपियाड विजेताओं को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दसवीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण : सरकार का इरादा कौशल विकास के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करने का है ताकि कौशल विकास संस्थान बड़ी संख्या में छात्रों को गुणवत्तापरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। इस उद्देश्य हेतु, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एस.वी.एस.यू.) को निजी संस्थानों को कौशल प्रमाणन हेतु संबद्ध करने की शक्तियां दी गई हैं।

गुरु-शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित: व्यवसाय और शिल्प में गुरु-शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि गुरु का कौशल अगली पीढ़ी के शिल्पकारों को दिया जा सके। एस. वी. एस. यू. ने वर्ष 2022-23 में गुरु-शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु और 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है।

कौशल प्रशिक्षण केंद्र : उद्योगों को कुशल, रोज़गार योग्य युवा उपलब्ध कराने के क्रम में एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा एस.वी.एस.यू. और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के सहयोग से अपने औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को नामांकित करेंगे और प्रशिक्षण की दोहरी ट्रैक प्रणाली का उपयोग करके उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। मूल्यांकन और प्रमाणन एस.वी.एस.यू. द्वारा किया जाएगा। इससे हरियाणा में रोज़गार के इच्छुकों और नियोक्ताओं के बीच की खाई भर जाएगी। 'दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली' के तहत वर्तमान में 306 व्यावसायिक इकाइयों में प्रशिक्षण के दौरान उद्योग के अनुभव के साथ कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

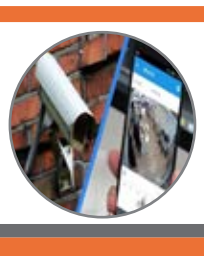

बजट में प्रदेश के 381 पुलिस स्टेशनों व 357 पुलिस चौकियों में सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने का लक्ष्य है। पुलिसकर्मियों के लिए 2,000 नए मकान बनाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दसवीं से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मुफ़्त टेबलेट दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

मत्स्य पालन के जरिए रोजगार

नीली क्रांति की दिशा में मत्स्य विभाग कई महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कृषि के क्षेत्र में ये बदलाव के संकेत है। अब मत्स्य पालन में रुचि लेने वाले लोग सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं का फायदा लेकर मत्स्य पालन व्यवसाय में आगे बढ़ सकेंगे। कम जमीन में प्रारंभ होने वाले इस व्यवसाय में अब ना तो मार्केट का झंझट रहेगा व ना ही प्रशिक्षण का दोनों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। जिसमें मत्स्य पालक इस व्यवसाय के साथ जुड़कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकर अब आर्थिक सहायता भी देगी।

सधन मत्स्य पालन योजना के तहत इस व्यवसाय को आगे जन-जन तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा के तहत तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी। इसमें मछली पालन के लिए पट्टे पर तालाबों को प्राप्त करना, मछली इकाई के निर्माण के लिए ऋण प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था। तालाब स्थलों की मिट्टी एवं पानी की जांच, योजना एवं अनुमान की तैयारी, सामान्य वर्ग के लिए अनुदान की राशि आदि प्रमुख है।

अब देहात के मत्स्य पालक पंचायती ज़मीन का उपयोग करके उसमें तालाब की खुदाई करके इस व्यवसाय के साथ जुड़कर अपनी जीविका चला सकेंगे। विभाग ने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाये हैं। विभाग प्रदेश में अनुपयोगी पड़ी 20 हजार हैक्टेयर भूमि को योग्य बना कर इसमें मछली व सफेद व झींगा का बड़े स्तर पर उत्पादन करायेगा। विभाग के अनुसार इसका फायदा खास तौर पर उन युवाओं को मिलेगा जिनके पास रोजगार का अभाव है। इसको लेकर इस बार विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। विभाग ने पिछले वर्ष 2 लाख 20 हजार मिट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था जबकि अब की बार इसे बढ़ाकर 2 लाख 30 हजार हैक्टेयर रखा है।

नीली क्रांति की तरफ बढ़ते इस व्यवसाय में विभाग 2500 एकड़ में पूरे प्रदेश में झींगा का उत्पादन करने की योजना को अंतिम रूप दे चुका है। सिरसा, हिसार , रोहतक ,भिवानी गुड़गांव ये वो जिले हैं जहां जमीन का बड़ा हिस्सा खारे पानी का है। इसमें विभाग सफेद झींगा को तैयार करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए विभाग लोगों को इस व्यवसाय को अपनाने की सलाह शिविर इत्यादि के माध्यम से दे रहा है।

विभाग के उप निदेशक ईश्वर ने बताया जो लवणीय, दलदली भूमि या अनुपयोगी भूमि है उसे सुधार करके उसे मत्स्य पालन योग्य बनाया जायेगा व मत्स्य पालन के अधीन लाया जायेगा। इसके लिए विभाग 100 प्रतिशत खर्च स्वयं वहन करेगी। तालाब खुदवाने , ट्यूबवैल व अन्य कार्यो के लिए मत्स्य पालकों को अनुदान देगा। इसमें 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग को व 60 प्रतिशत महिलाओं और अनुसूचित जाति को मत्स्य पालन में अनुदान दिया जायेगा। यह कल राशि 14 लाख के करीब होगी।

उप निदेशक ईश्वर ने बताया मत्स्य पालन में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। विभाग 1500 सौ एकड़ अनुपयोगी ज़मीन को पंचायतों के माध्यम से इस बार मत्स्य पालकों को पटटे पर देगा व 600 एकड़ जमीन मत्स्य पालन के निजी क्षेत्र को दी जायेगी। इसके लिए विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत यह अनुदान व अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान रखा है। इसमें 7 लाख रूपए की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। इस मत्स्य पालक तालाबों की खुदाई के लिए , पाईप लाईन के लिए प्रावधान है। मत्स्य पालकों को सौर उर्जा पंप सैट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

उन्होंने बताया मत्स्य पालकों को किसी भी प्रकार की मछलियों के विक्रय में तकलीफ ना हो इसको लेकर गुरुग्राम में अत्य आधुनिक मंडी बनाने पर विचार किया जा रहा है। उनके अनुसार जिला भिवानी के गांव गरवा में मछली उत्कृष्ता केंद्र की स्थापना की जायेगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अर्न्तगत अत्योदय परिवार लाभार्थियों को मछली पालन के व्यवसाय से जोड़ा जायेगा। अधिसूचित पानियों मे लुप्त होती मछली प्रजातियों के बीज का संचय एवं संर्वधन किया जायेगा।

-संवाद ब्यूरो

किसानों के जीवन में खुशहाली लाती
पीएम कुसुम योजना

संगीता शर्मा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार किसानों को कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार द्वारा नई तकनीकों पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है जिसका प्रदेश के किसान खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान' (पीएम-कुसुम) के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने में हरियाणा सोलर वाटर पम्पों के संचालन के साथ देश का अग्रणीय राज्य है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधा के लिए सोलर पम्प स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की तरफ से 45 फीसद व केंद्र सरकार की तरफ से 30 फीसद सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस तरह से कुल 75 फीसद आर्थिक सुविधा सरकार की तरफ़ से प्रदान की जाती है। किसानों को महज अपनी तरफ से 25 फीसद ही खर्च करना होता है।

किसानों की आय बढ़ाने में उपयोगी योजना

सरकार की यह योजना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि आमतौर पर किसानों को सिंचाई संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में कृषि योग्य लगभग 80 लाख एकड़ भूमि है। इसमें से 75 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई हो पाती है। शेष भूमि पर सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए सोलर पंप किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प हैं। सोलर पंप लगाने से किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोडमैप तैयार

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा में आज से सात वर्ष पहले न के बराबर कार्य था। वर्ष 2014 तक केवल 492 सोलर पम्प ही लगवाए गए थे। वर्तमान सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रोडमैप तैयार किया। इसके पहले चरण में 50 हजार सोलर पम्प सेट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले सात वर्षों में 25,897 सोलर पम्प सेट लगाए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए 22 हजार सोलर पम्प देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 15 हजार सोलर पम्प प्रदान किए जा चुके हैं तथा शेष 7 हजार सोलर पम्प मार्च 2022 तक दे दिये जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 22-23 में 50 हजार सोलर पम्प लगाए जाएंगे।

सोलर पंप लगाकर किसान कमा रहे हैं मुनाफ़ा

महेंद्रगढ़ की सुमित्रा देवी ने भी सरकार की 'पीएम कुसुम योजना' का लाभ उठाते हुए भागदाना गांव में पांच एकड़ ज़मीन की सिंचाई के लिए 10 एचपी का सोलर पंप लगाया है। इस योजना का लाभ उठाकर सुमित्रा देवी ने न केवल फसल उत्पादन बढ़ाया है, बल्कि उत्पादन लागत में भी कटौती की है। सुमित्रा देवी अब राज्य के कई अन्य किसानों के लिए भी आदर्श बन चुकी हैं। सुमित्रा देवी कहती हैं, चूंकि डीजल पंप की लागत बहुत अधिक है, इसलिए मैं केवल एक फसल की खेती करती थी। तब मुझे पीएम-कुसुम योजना के बारे में पता चला, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें सोलर पंप लगाने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। मैंने इसके लिए आवेदन किया और अपने खेत में 10 एसी एचपी का सबमर्सिबल पंप लगवाया। अब मैं एक से अधिक फसलें उगा सकती हूं और दिन में खेतों की सिंचाई कर सकती हूं। इसके अलावा, इसे चलाने की कोई लागत नहीं है और सौर पंप की रख-रखाव लागत नगण्य है।

योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन

जो किसान सोलर वाटर पर्मपिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, उन्हें http://saralharyana.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की कोई भी हार्ड कॉपी विभाग/हरेडा द्वारा स्वीकृत नहीं की जाएगी।

पीएम कुसुम योजना के लाभ

- जोखिम मुक्त आय प्रदान करता है।
- अत्यधिक दोहन को रोकने की क्षमता है।
- निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करता है।
- कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद ।

बता दें कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा ऐसा राज्य है जहां वर्ष के दौरान 320 दिन सूर्य की रोशनी मिलती है, जो सौर ऊर्जा का प्राकृतिक स्त्रोत है। गुजरात के बाद हरियाणा देश का दूसरा राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। अब अन्य राज्य भी इस योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

प्रदर्शनी में पहुंचे इनामी पशु

पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भिवानी में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पशुपालक लाखों रुपए की मुर्राह भैंस व साहीवाल नस्ल की गायों को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौके पर पहुंचकर पशुपालकों का हौसला बढ़ाया व विजेताओं को इनाम वितरित किये।

प्रदर्शनी में रैंप पर नगाड़ों, बीन, ढोलक की ताल पर डांस करते घोड़ों व ऊंटों ने दर्शकों का मन मोह लिया था। घोड़ों की दौड़ व ऊंटों की सवारी का नजारा देखा गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के विशेषज्ञों ने लोगों को मुर्गी पालन, बकरी पालन, शुकर पालन के बारे में सरकार द्वारा दी जाने वाले योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

हिसार के पृथ्वी नाथ गौशाला पावड़ा की गाय आकर्षण का केंद्र थी। शेखपुरा से आए पशुपालक संदीप ने बताया कि उनके पास लाखों की कीमत के झोटे हैं। सिरसा के जगतार ने बताया कि उनके देसी झोटे अनमोल की कीमत ढाई करोड़ लग चुकी है मगर वह बेचने के लिए तैयार नहीं है। रोहतक के देवेंद्र कोच ने बताया कि वे अपने पशुओं को बच्चों की तरह पालते हैं। उनके पास जो मुर्राह झोटा बादल है वह

2020 और 2021 में हरियाणा चैंपियन का खिताब जीत चुका है। जींद के गांव अटेली के दिलेर का झोटा जिसकी किमत 11 करोड़ बताई गई, लोगों क आकर्षण का केंद्र रहा।

सभी जिला नागरिक अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में विश्राम सराय की सुविधा होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर भी बनेंगे।

35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल 'क्राफ्ट्स मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित होगा। इस दौरान जम्मू कश्मीर थीम राज्य होगा तथा उज्बेकिस्तान विदेशी सहयोगी होगा। मेले का समय बाद दोपहर 12.30 से 9.30 बजे तक रहेगा।

प्रेम व सौहार्द बढ़ाने का पर्व होली

फाल्गुण मास में मनाया जाने वाला 'होली' पर्व रंगों का पर्व है। इस पर्व पर प्रकृति की छटा सुहावनी होती है। सर्दी की विदाई का समय होता है और बसन्त चरम पर होता है। हरियाणा में होली का शुभारंभ माघ महीने की पूर्णमासी को 'होली का डांडा' गांव के बीच रोपकर होता है। इस दिन को 'डांडा-रोपणी' भी कहा जाता है। इस दिन संत शिरोमणी गुरू रविदास महाराज का जन्मोत्सव भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 'डांडा' रोपकर महीने भर चलने वाले होली के इस अनुपम, अदभुत व अनूठे त्योहार की शुरुआत कभी बड़े धूम-धाम से होती है।

कन्याएं और महिलाएं होली मनाने की तैयारी पूरे महीने करती हैं। पशुओं के गोबर से बने ढाल और बिडकुले चांद-सूरज बनाकर उनको जेवड़ी में पिरोकर माला बनाई जाती है। 'डांडा रोपणी' के साथ ही बालिकाएं, युवतियां और वृद्धाएं होली के गीत गाने शुरू कर देती हैं। रात को बगड़ की सारी छोरी-छापरी, बहुएं और वृद्धाएं घर का सारा काम-काज पूरा कर एक जगह इक्कठी होकर होळी के गीत गाती हैं। होळी का यह लोकगीत तो गांव-देहात में गाया जाता है:

"होळी ए तेरो लाम्बो टीको,
लाम्बा डस की डोरी।
डोर हलावै म्हारो चीनू बीरो,
जैकी की बहूवड़ गोरी।"

इस गीत में महिलाएं घर के सभी पुरुषों का नाम ले-लेकर के गीत गाती और खूब नाचती हैं।

छोरे मारूंगी ढूंगा, देही तोड़ ढूंगी।
जिब आवै तेरा ताऊ, हांडी रोड़ ढूंगी।
सब मिलकर होली के गीत गाती हैं:
आज बिरज म्ह होली हो रसिया।
भर पिचकारी मोरी छतिया पै मारी,
माला की आब उतारी हो रसिया।

फाग के राग में मस्ती का आलम सातवें आसमान पर होता था :

काच्ची इमली गदराई साम्मण म्हं
बूढ़ी मस्ताई फाग्गण म्हं।
कहियौ रै उस कंथ मेरै नै,
जिन हाल्यी ले ज्या फाग्गण म्हं।

बगड़ की खुली जगह पर जमा होकर गांव की महिलाएं और कन्याएं सांग खेलती हैं। इन सांगों में प्रायः सभी किसी न किसी का अभिनय करती थीं। इन सांगों में पुरुषों की उपस्थिति वर्जित थी। इन सांगों में महिलाएं अपनी अल्हड़ भावनाओं को संपूर्ण स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करती थीं। महिलाएं खुलकर अपने मन का गुब्बार निकालती थीं।

इसी गजब की बहू बणूंगी,
जिब सोलहा सिंगार करूं।
छोरां म्ह रूका पड़ज्या,
बूढ़ां तक बी मार करूं।।

धवल चांदनी में गोरियों की पायल की रुनझुन वातावरण को संगीतमय बना देती थी :

रसिया को नारी बनाओ री,
रसिया को नारी बनाओ,
कमर म्हं लहंगा गले म्हं चोली,
चूंदड़ सीस उढ़ाओ री।

'होली-पूजन' फागण की पूनम को किया जाता है। होली पूजन प्रकृति का पूजन है, पकी हुई फसल का पूजन है, गो पूजन है और परिवार की खुशहाली का पूजन है। तभी तो इस दिन महिलाएं सज-धज कर पूजा की थाली में जौ-गेंहु की बालियां और पानी का लौटा लेकर तथा जेळे (बिडकुलों और ढालों से बनी मालाएं) हाथ में लेकर अपने छोटे बच्चों के साथ होली पूजन के गीत गाती हुई जाती हैं। महिलाएं पहले पानी से होली को सींचती है फिर पूजा की थाली की सामग्री होली पर चढ़ाती हैं फिर कच्चे सूत से होली को पूरती हैं। फिर जो जौ गेंहु की बालियां पूजती हैं और सुबह से रखा हुआ उपवास होली पूजन के बाद खोलती हैं। होली पर जेळे (बिडकुलों और ढालों से बनी मालाएं) रखकर अपने से बड़ी महिलाओं के पैरों में धोक खाकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं।

रात को लगभग 8-9 बजे तक होली मंगलाई जाती है। होली मंगलाने के बाद डांडे (प्रहलाद का प्रतीक) को बिना जले उखाड़कर किसी जोहड़ या 'पानी की खेल' में डाल इस अवसर गीत गाती हैं:

होली माता होलका, तन्नै कोण मंगलावै,
म्हारो छोरो गाभरू, तन्नै वो ही मंगलावै।

महिलाएं मंगलती होली पर पानी डालने के बाद अपने पति और देवरों पर पानी डालकर मस्ताने फागण के एक अनुपम पर्व धुलंडी का आगाज कर देती है। होली के अगले दिन सब लोग एक दूसरे को गुलाल व रंग लगाते हुए साल भर के गिले शिकवे दूर करते हैं। जो दूर होते हैं वे भी अपने या अपने चाहने वालों के घर जाते हैं और जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूल जाते हैं। शाम को मिल बैठकर मिठाई व अन्य पकवान खाते हैं और एक बार फिर नए सिरे से रंगों का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं।

- भूप सिंह 'भारती'

सुण छबीले बोल रसीले

लेखक बणन की राह पर छबीला

रसीले, कहा और लिखा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज, देह होती है तो साहित्य उसकी आत्मा। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी समाज या राष्ट्र के बारे में जानना हो तो उसका साहित्य पढ़ लीजिए। इतना ही नहीं यह भी कहा जाता है कि साहित्य में वह शक्ति होती है, जो तोप और तलवार में नहीं होती।

- छबीले भाई तूं कहणा के चाहवै सै?

- मैं न्यू कहणा चाहूं सूं। अक ये तोप और तलवार तो म्हारे बसकी नहीं। क्यों ना मैं भी कोई किताब लिख ल्यूं और साहित्यकार बणजाऊं?

- डटज्या आचार्य महाबीर प्रसाद, डटज्या। पहली बात, वो बख्त कुछ और था, ईब बख्त कुछ और सै। पहल्यां इक्का-दुक्का लेखक, कवि, सांगी और साहित्यकार होया करते। लोग उनकी सुणा करते और उनपै अमल भी करा करते। खास बात यो थी अक वे जो लिख्या-पढ्या और घड्या करते वो समाज हित में, राष्ट्रहित में या धर्म-कर्म हित में तर्कसंगत और सटीक बात हों थीं। उनका असर था और तो और जवाहरलाल बरगे भी उनतैं प्रभावित होया करते।

- हां रसीले, दादा लख्मी की बातां नै आज भी लोग याद करैं सैं। बड्डे बूढ़े तो उनकी रागनी भी जाणै सैं। उनकी कही ओड़ बातां का आज ताहीं असर सै। लोग टैम-टैम पर याद करैं सैं। बोहत गहरी बात कहा करते। एक दो रागनी तो इसी सैं अक उनका पूरा अर्थ तो शायद आज भी किसे नै ना बेरा। थोड़ी सी उम्र में ए दादा लख्मी अमर होग्या।

- हां भाई, तूं के साहित्यकार बणैगा। ईब तो फेसबुक पै साहित्कार और प्रवचन देण आल्यां की लाइन लागरी सै। दूसरी बात यो सै अक तूं कोई नेता, अफसर, उद्योगपति या एक्टर नहीं, अक तेरा लिख्या होया लोग पढ़ैंगे। लिख लेगा तो उसनै छापैगा कौण? प्रकाशक किताब छापण के मोटे रुपए लेगा। छप गई तो उसनै खरीदैगा कौण? वे सारी किताब तनै आपणा नाम लिख-लिखकै सादर सप्रेम भेंट करणी पड़ैंगी। भेंट कर भी देगा तो कोई पढ़ै कोन्या। क्योंकि किसे धोरै इतणा टाइम कोन्या। सब आपणे आपे नै विद्वान समझैं सैं। तेरी कौण सुणैगा?

-पर रसीले, मैं जो लिखूंगा वो गदर लिखूंगा। समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए जी तोड़ लिखूंगा। लोगां नै मेरा लिख्या होया पढ़णा और सुणना पड़ैगा। जो ना पढ़ैंगे तो वे मूर्ख कहलावैंगे।

- छबीले मनैं लागै सै, मूर्ख तूं हो लिया। आज-काल किताब वे लिख्या करैं जिनकी रोजी-रोटी पक्की हो। दस आदमी जाणते हों, जो तेरी लेखनी नै पढ़कै दस-बीस लोग वाह-वाह करैं। बेशक तनै किताब में आपणी रामायण लिख राखी हो।

- देख रसीले, तूं नहीं चाहता अक मैं साहित्यकार बणूं। यो आच्छी बात कोन्या।

- भाई मैं तेरा जी तोड़ण वाली बात कोन्या करता। समाज की कड़वी सच्चाई सै अक जै तूं प्रभावशाली सै तो तेरी सुणन आले बीस पाज्यांगे। नहीं सै, तो तेरी सुणने वाला कोय ना पावै।

-अरै रसीले, मैं किताब में साहित्य की गंगा-जमुना बहा द्यूंगा। राष्ट्रहित में और समाज हित में साहित्य का कुतुबमीनार खड़ा करद्यूंगा। उस किताब में आपणी प्रेम या विरह कथा कोन्या लिखूं। राष्ट्रीय इतिहास, लोक संस्कृति, सभ्यता, रीतिरिवाज, परंपरा, प्रकृति, भाषा, सुविचार और विकास की बात करूंगा।

- लिख ले छबीले, लिख ले। मन में पक्की धार राखी सै तो जरूर लिख, कामयाब होज्यागा। किताब छपणे के बाद कितोड़ किसी संस्था तैं कह सुणकै तनै सम्मानित भी करा देंगे। और नहीं तो हरियाणा सरकार साहित्कारां नै सम्मानित तो करैए सै।

पीछे से आवाज आई- ओ रमलू के बाबू, आज्या लाइट आगी। गंडासे पै यो ईंख का भरोटा काट ले, और डांगरा नै पाणी दिखा दे। मैं बावलां कै गीतां में जा सूं।

- मनोज प्रभाकर

उड़े रे उड़े गुलाल उड़े

चंग, ढोल और थाप चहुं ओर सुने रे सुने,
होली आई रे, आयी होली आई।

गीतों की राग मन बहलायें रे बहलायें
रंग ऐसे उड़े, मन से मन मिले रे मिले,
होली आई रे, आई होली आई।

बच्चे, बूढ़े सब में मस्ती की उमंग उठे रे उठे
अपनों संग कितने दिनों बाद मिले रे मिले,
होली आई रे, आई होली आई।

सुबह-शाम ऐसे बीते रे बीते
रंग-बिरंगे रंगों में दिन बीते रे बीते,
होली आई रे, आई होली आई।

संध्या होते ही ढप और चंग बाजे रे बाजे
चटपटी मिठाइयों का स्वाद आया रे आया,
होली आई रे, आई होली आई।

जात-पात के सब बैर मिटे रे मिटे
शत्रुओं के हाथ मित्रता को बढ़े रे बढ़े,
होली आई रे, आई होली आई।

-नरेंद्र वर्मा

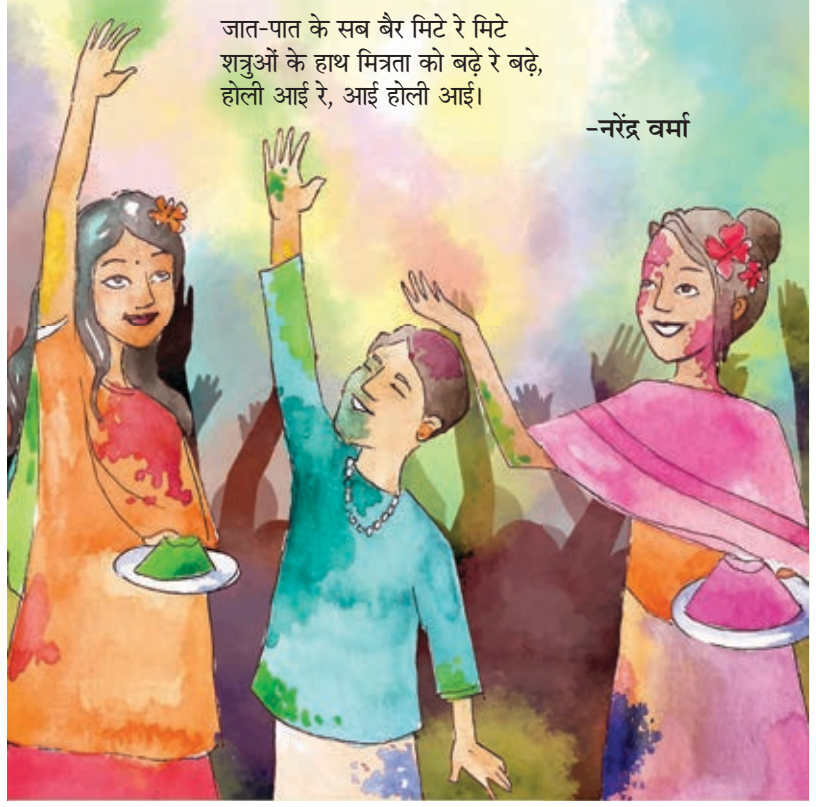

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com